



गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)

GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

पंजीकृत कार्यालय:

गेल भवन

16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066, इंडिया

Regd. Office:

GAIL BHAWAN

16 BHIKAJI CAMA PLACE, R.K. PURAM
NEW DELHI-110066, INDIA

फोन/PHONE : +91 11 2618 2955

फैक्स/FAX : +91 11 2618 2955

ई-मेल/Email: info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2025

August 08, 2025

- | | |
|---|---|
| 1. Listing Compliance
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Scrip Code: GAIL-EQ | 2. Listing Compliance
BSE Limited,
Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532155 |
|---|---|

Sub.: Newspaper Publication of Dispatch of Notice and Annual Report of the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of GAIL (India) Limited

Dear Sir/Madam,

This is in compliance of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

With reference to the subject cited above, please find the attachment.

The above is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

(Mahesh Kumar Agarwal)
Company Secretary

Encl: As above

TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED																			
		CIN: L29199HR1956PLC033107																	
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana)																			
Tel No.: 0129-4960482, Website: www.talbro.com, Email: seema_narang@talbro.com																			
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025																			
Particulars	CONSOLIDATED				STANDALONE				(Rs. in lacs)										
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended												
	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25											
	Unaudited	Audited (Refer Note 2)	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited (Refer Note 2)	Unaudited	Audited											
Total Income from Operations	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,473.03	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,590.83											
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27											
Exceptional items	-	-	-	-	-	-	-	-											
Profit/(Loss) before tax	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27											
Net Profit/(Loss) after tax	2,219.64	2,658.10	2,061.47	9,443.27	1,819.79	2,125.18	1,756.96	7,787.25											
Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax)	3,417.71	2,231.97	4,029.54	9,977.75	3,017.14	1,693.26	3,725.93	8,318.83											
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56											
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for the period - not annualised)																			
Basic (Rs.)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62											
Diluted (Rs.)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62											

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and www.nseindia.com) and on Company's website (www.talbro.com).
- These standalone and consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Talbros Automotive Components Limited ("the Company") at their respective meetings held on 07 August 2025. The figures for the quarter ended 31 March 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. The financials results for the quarter ended 30 June 2025 have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company. Mr. Anuj Talwar, JMD is duly authorised by Board to sign the financial results for submission to stock exchanges.

For Talbros Automotive Components Limited
Sd/-
Anuj Talwar
Joint Managing Director
DIN : 00628063

Date : August 07, 2025
Place : Gurugram

टैरिफ बढ़ने के बाद भी चढ़े बाजार

देसी संस्थागत निवेशकों की रिकॉर्ड खरीद, पुतिन-ट्रंप के बीच बैठक की संभावना से शेयर बाजारों को अंततः करीब एक फीसदी गिरावट से उबरने में मदद मिली

सुंदर सेतुरामन मुंबई, 7 अगस्त

घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की मजबूत खरीदारी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के बीच अगामी शिखर सम्मेलन से उम्मीदें लगाते हुए भारतीय बाजार गुरुवार को तीन महीने के निचले स्तर से उबर गए और बढ़त के साथ बंद हुए।

भारत के निरंतर रूसी ऊर्जा की खरीद के जवाब में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करने के अमेरिका के कदम ने निवेशकों का मनोबल प्रभावित हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स लगभग एक फीसदी गिरकर 79,811 पर चला गया जो 9 मई के बाद सबसे निचला स्तर है। हालांकि यह 79 अंक (यानी 0.1 फीसदी) की बढ़त के साथ 80,623 पर बंद हुआ।निफ्टी भी तीन महीने के निचले स्तर 24,344 पर पहुंच गया, लेकिन फिर गिरावट की भरपाई करते हुए 22 अंक (0.09 फीसदी) की बढ़त के साथ 24,596 पर बंद हुआ।बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल इंडा रुपये बढ़कर 445.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।

इस बढ़त को डीआईआई से सहाय मिला जिन्होंने घरेलू शेयरों में 10,864 करोड़ रुपये का निवेश किया जो 7 अप्रैल के बाद से उनकी एक दिन की सबसे बड़ी खरीद है।

असूचीबद्ध फर्मों के लिए आरटीए की अलग यूनिट का प्रस्ताव

बाजार नियामक ने गुरुवार को सूचीबद्ध कंपनियों और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) की प्रविधियों को अलग करने का प्रस्ताव रखा।

सूचीबद्ध कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को आरटीए द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सेबी के अधीन होंगी जबकि गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेवाएं कंपनी मामलों के मंत्रालय के दायरे में आएंगी।

नियामक ने कहा कि सभी क्षेत्रों में डीमैट के महत्व को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस की गई। अभी आरटीए लगभग 35,000 गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या करीब 4,000 है।

सेबी ने गैर-सूचीबद्ध कारोबारों के लिए आरटीए द्वारा एक अलग व्यावसायिक इकाई का प्रस्ताव रखा है। बाजार नियामक ने आरटीए के लिए समान परिभाषा का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें वर्गीकरण को हटा दिया गया है और नेटवर्थ की गणना को संशोधित किया गया है।एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव धोखाधड़ी रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु एमडी, सीईओ और अन्य ऐसे प्रबंधन कर्मियों पर अधिक जिम्मेदारी के लिए तंत्र स्थापित करने का है।

बीएस

भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से स्थिर रहा रुपया

अंजलि कुमारी मुंबई, 7 अगस्त

बुधवार को भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका के 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित डॉलर बिक्री के हस्तक्षेप के कारण गुरुवार को रुपया स्थिर रहा। डीलरों ने यह जानकारी दी। भारत पर अब ब्राज़ील के बराबर अमेरिका ने सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। यह अतिरिक्त टैरिफ 28 अगस्त से लागू होगा।स्थानीय मुद्रा 87.71 प्रति डॉलर पर बंद हुई जो एक दिन पहले के बंद भाव 87.74 प्रति डॉलर के मुकाबले करीब-करीब स्थिर है।

आईएफए ग्लोबल के मुख्य कार्याधिकारी अभिषेक गोयनका ने कहा, रुपये में नई तेजी की पुष्टि के लिए डॉलर-रुपये का 87.95 -88.00 के स्तर से ऊपर बंद होना जरूरी है। हालांकि हालिया गतिविधियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्रीय

इसके उलट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 4,997 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

रूस ने घोषणा की है कि वह पुतिन-ट्रंप बैठक के लिए अमेरिका के साथ जगह पर सहमत हो गया है और उसने पुतिन तथा ट्रंप के दूत स्टीव वित्कोफ के बीच हाल में हुई बातचीत के बाद प्रमुख मसलों पर चर्चा शुरू कर दी है।

अधिकांश वैश्विक बाजारों में भी

बैंक रुपये को और अधिक गिरने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इस कदम से चुनिंदा भारतीय निर्यातों पर कुल शुल्क प्रभावी रूप से 50 फीसदी हो गया है।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली ने कहा, टैरिफ के आर्थिक प्रभाव चिंता का विषय है क्योंकि बढ़ते व्यापार तनाव के कारण भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान में संभावित रूप से कमी आ सकती है।।

गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात (वॉल्यूम में) में अमेरिका का योगदान करीब 4 फीसदी था जो वित्त वर्ष 2024 में करीब 1 फीसदी रहा था जबकि रूसी आयात भारतीय तेल आयात का लगभग एक तिहाई है।

मंगलवार को ट्रंप ने भारत पर रूस के युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे महीनों की बातचीत के बाद व्यापार तनाव और बढ़ गया।

ये टैरिफ ट्रंप की 8 अगस्त की समयसीमा से पहले ही लगाए गए हैं जब उन्होंने रूस को यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया था। मोतीलाल

ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (वैल्थ मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमका ने कहा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावादित्ता से बाजार में उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि बातचीत के लिए अभी भी 20 दिन का समय है। हमें उम्मीद है कि बाजार सीमित दायरे में रहेगा और अमेरिका-रूस शांति वार्ता के घटनाक्रम, अमेरिकी टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया और घरेलू आय के अनुमानों पर कड़ी नजर रहेगा।

बाजार में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात कमजोर रहा। बीएसई पर 2,297 शेयरों में गिरावट और 1,751 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स की बढ़त में एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें 0.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, उसके बाद इंटरनल का स्थान रहा, जिसमें 0.9 फीसदी का इजाफा हुआ। बेंट कूड 0.6 फीसदी की बढ़त के साथ 68.2 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

रेलिंगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ शोध उपाध्यक्ष अजित मिश्र ने कहा, निफ्टी 24,450 के समर्थन स्तर से ऊपर बना रहा जिससे एक प्रमुख आधार के रूप में इसकी मजबूती की पुष्टि हुई।पिछली एकीकृत सीमा के निचले स्तर ने तेजी को जम दिया। 24,800 से ऊपर एक निर्णायक कदम से 25,000 के स्तर की ओर उछाल का रास्ता खुल सकता है।

साई अरविंद और पुनीत वाधवा मुंबई/नई दिल्ली, 7 अगस्त

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारतीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और बढ़ सकती है। उभरते बाजारों (ईएम) की तुलना में उनकी भारत से पहले से ही सबसे अधिक निकासी हो रही है।

ट्रंपक स्टॉक ब्रोकिंग के अनुसार जुलाई के अंत तक भारत से एफपीआई ने 10.3 अरब डॉलर की बिकवाली की है।एनएसई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 13 कारोबारी सत्रों में वैश्विक फंडों ने 40,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।

विश्लेषकों ने इस रुझान के लिए मोटे तौर पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने बुधवार को रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ दोगुना यानी 50 फीसदी कर दिया।

उनका मानना ​​है कि जून तिमाही में कंपनियों की कमजोर आय और जेन स्ट्रीट के घटनाक्रमों के बीच भारतीय बाजारों (निफ्टी 50) का मूल्यांकन एक साल आगे की आय के 22.3 गुना पर होने से पिछले कुछ हफ्तों में भी भारत के प्रति एफपीआई का मनोबल प्रभावित हुआ है।विश्लेषकों का कहना है कि फिर भी भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश की आवक को लेकर उम्मीद की एकमात्र बहुरिण अमेरिकी फेडरल रिजर्व का दर कटौती है। साथ ही, अगली कुछ तिमाहियों में भारतीय कंपनियों की आय में सुधार होने पर तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन में सहजता से भी उनका निवेश बढ़ सकता है।

आईएनवीऐसेट पीएमएस में पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग के अनुसार देश की संरचनात्मक मजबूती के कारण दीर्घकालिक पूंजी भारत में निवेश के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है।लेकिन निकट भविष्य में एफपीआई सतर्क रह सकते हैं।स्पष्टता होने तक जोखिम-प्रतिफल उन कंपनियों में मिल सकता है जो नकदी समृद्ध हैं और घरेलू हैं।

डीआरचौकसी फिनसर्व के प्रबंध निदेशक देवेन

सालाना निरीक्षण के नियमों में संशोधन

सेबी ने गुरुवार को शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के सालाना निरीक्षण में सुधार के उपायों की घोषणा की। 1 दिसंबर से सभी मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्टि्यूशंस (एमआईआई) जैसे स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी द्वारा अलग-अलग निरीक्षणों के बजाय एक ही समय में संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। एमआईआई के पास निरीक्षणों से हासिल टिप्पणियों के लिए सूचना साझा करने की एक व्यवस्था होगी।इसके अलावा, मध्यस्थों के सालाना निरीक्षण के चयन मानदंडों में भी ढील दी गई है और निरीक्षण का दायरा केवल उन अग्रणी 25 संस्थाओं पर होगा, जिन पर उच्च और आवर्ती गुणवत्ता है याजिनके खिलाफ निवेदकों की शिकायतें ज्यादा हैं। अन्य संस्थाओं का निरीक्षण तीन वर्षों में कम से कम एक बार किया जाएगा।

बीएस



गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं (इकतालीसीवां) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि एजीएम की सूचना में तथा निर्धारित व्यवसायों का संचालन किया जा सके। 3बी और एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की 41वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी वॉर्लेसिपेट (डीपी) या आरएसएटी के पास पंजीकृत है। इसे कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com), स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (रिमोट ई-वॉटिंग) सुविधा प्रदान करने वाली एक्सबी (www.evotingindia.com) पर भी होस्ट किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (संबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम (एजीएम) का उपयोग करके 41वीं एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव है। कंपनी ने रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डिपॉजिटरी अर्थात सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई-वॉटिंग अवधि सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2025 (प्रातः 9:00 बजे) (आरएसएटी) से आरंभ होती है और गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त, 2025 (प्रातः 5:00 बजे) (आरएसएटी) को समाप्त होती है।

कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 2025** को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में पंजीकृत होए (क) रिमोट ई-वॉटिंग; (ख) वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी; और (ग) एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वॉटिंग मोड के माध्यम से वोट करने की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से वोट करना चाहे तो वे, वीसी/ओवीएम के माध्यम से भी वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वार्षिक आम सभा में दौरान उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एक बार जब सदस्य द्वारा रिमोट ई-वॉटिंग या ई-वॉटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो सदस्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के लिए रिमोट ई- वॉटिंग की सुविधा अंतिम तिथि तक www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओ.ए वी.एम. की सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई- वॉटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं किया है और अतःअन्य रूप से ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं है, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वॉटिंग के लिए निर्देशों का संदर्भ लें, जो एजीएम नोटिस का एक हिस्सा हैं।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वॉटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वॉटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए. विंग, 25वीं मंजिल, मेरधान प्लसएक्स, मफलताल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पर्ले (पुणे), मुंबई - 400013 को भेजी जा सकती है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

यदि कोई व्यक्ति ई-वॉटिंग के लिए सीडीएसएल/एमएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो रिमोट ई- वॉटिंग या ई-वॉटिंग के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का शेयर प्राप्त करता है और कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिफ भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह अपने शेयरधारिता विवरण के साथ shareholders@gail.co.in या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी **शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे** से एजीएम की समाप्ति तक शेयरधारकों के लिए एजीएम की कार्यवाही का एकतरफा लाइव वेबकास्ट की सुविधा प्रदान कर रही है। आप इसे गेल की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर देख सकते हैं।

इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली है, जो निर्धारित तिथि 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और **7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक** छह महीने की अवधि के लिए दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी भी कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस अवधि के पास आज की तारीख तक संबंधित अनुरोध भी शामिल हैं। केवल डी-मैट मोड में जारी की जाएगी। ऐसे हस्तांतरण- सह- डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

सदस्यों को अपना अनुरोध/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए आरएसएटी और कंपनी की निडिई ई-मेल आईडी क्रमशः admin@cdslindia.com और shareholders@gail.co.in है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:08.08.2025
ई-मेल: shareholders@gail.co.in

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए एएसडी।
(महेश कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय: गेल भवन, 18, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110068
फ़ोन: 011-26182955, फ़ैक्स: 011-26188941 (सीलबॉक्स: L40200101-198403-10896)

www.gailonline.in **#EmergingPossibilities** Follow us on [f](#) [t](#) [in](#)

आईपीओ से पहले पूंजी जुटाएगी भारतपे

अजिंक्य कावले मुंबई, 7 अगस्त

वित्त वर्ष 2025 में मुनाफा दर्ज करने वाली फिनटेक फर्म भारतपे अपने संभावित आईपीओ से पहले पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी का आईपीओ वित्त वर्ष 2026 के बाद बाजार में लाने का इशारा है। भारतपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी ने यह जानकारी दी। नेगी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'आईपीओ इस वित्तीय वर्ष में नहीं आने वाला है। लेकिन उसके बाद संभावना है। इससे पहले एक प्री-आईपीओ (फंडिंग) राउंड होगा। यह कब होगा, हम इस पर विचार करेंगे।' उन्होंने आईपीओ के बारे में कोई समय-सीमा या राशि जुटाने की योजना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र में बाजार की धारणा समझने के लिए आने वाले सभी फिनटेक आईपीओ पर नजर रखेंगे।

अपनी व्यापक रणनीति के तहत भारतपे ने अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) इकाई ट्रिलियनलोन्स में हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर ली है और अगले दो से तीन वर्षों में इस इकाई का पूर्ण स्वामित्व हासिल करने की योजना बना रही है। शेष हिस्सेदारी एनडीएक्स फाइनेंशियल



नलिन नेगी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतपे

सर्विसेज के पास है। ट्रिलियनलोन्स को भारतपे ने प्रमोट किया है, जो रेजिलिएंट इनोवेशन्स का ब्रांड नाम है। नेगी ने कहा कि संभावित आईपीओ से पहले उनका लक्ष्य पूरी तरह से शुद्ध लाभ का कारोबार बनाना है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के साथ-साथ उपभोक्ता खंड सहित अन्य क्षेत्रों का भी महत्वपूर्ण राजस्व योगदान हो। इस साल जनवरी में नेगी ने कहा था कि कंपनी की

18 से 24 महीनों में सूचीबद्ध होने की योजना है।

वित्त वर्ष 2025 में प्रदर्शन

यह योजना ऐसे समय बनाई जा रही है जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 6 करोड़ रुपये का समायोजित कर-पूर्व लाभ दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में उसे 342 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

दिल्ली की इस कंपनी ने कहा कि उसका एबिटा (ईसांप खर्च को छोड़कर) वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 141 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि वित्त वर्ष 2024 में उसे 209 करोड़ रुपये का एबिटा घाटा हुआ था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 1,667 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्जित 1,426 करोड़ रुपये से 16.9 प्रतिशत अधिक है।

यूनिटी स्मॉल फाइनैस बैंक में हिस्सेदारी रेजिलिएंट इनोवेशन्स की यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नियामकीय शर्तों के अनुसार कंपनी को बैंक की लिस्टिंग हो न हो, 2029 तक बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 10 प्रतिशत करनी होगी। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अनुसार, भारतपे को बैंक संचालन के आठ वर्षों के भीतर अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी।

‘लंबी अवधि में फायदे के लिए अल्पावधि कष्ट सहना उचित’

दीपक पटेल

नई दिल्ली, 7 अगस्त

जेसीबी इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के मुद्दे पर गुरुवार को कहा कि दीर्घावधि लाभ पाने के लिए अल्पावधि कष्ट सहना पड़ता है और निर्माण उपकरण उद्योग इसके लिए तैयार है। जेसीबी ने वर्ष 2024 में 14,000 यूनिट का निर्यात किया, जिसमें 10,000 निर्माण उपकरण अमेरिका भेजे गए थे। शेट्टी शुक्रवार को भारतीय निर्माण उपकरण निर्माता संघ (आईसीईएमए) के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। भारतीय निर्माण उपकरण उद्योग का आकार लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अमेरिकी सरकार के इस कदम से चिंतित हैं, तो शेट्टी ने कहा, 'हां।' उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'पिछले चार साल दुनिया भर में जेसीबी के निर्यात के लिए बेहतरीन रहे हैं। इससे पहले, जेसीबी केवल लगभग 2,000 मशीनों का निर्यात करती थी। अगर हम पिछले पांच वर्षों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि हमारा निर्यात कई गुना बढ़ा है। हम अब 135 देशों को निर्यात करते हैं।' अमेरिका के साथ टैरिफ और व्यापार के मुद्दों पर उन्होंने कहा, 'एक उद्योग के तौर पर हम बहुत खुले हैं। हम अपनी सरकारों के हाथ खुले रखना चाहते थे, इसलिए हमने वाणिज्य मंत्रालय से कहा कि दोनों पक्षों द्वारा आयातित निर्माण उपकरणों पर कोई शुल्क नहीं होना चाहिए ताकि समान अवसर उपलब्ध हों। हमें अपनी मशीनों की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है।' उन्होंने अन्य संभावित बाजारों की ओर भी इशारा किया, जिन पर कंपनी निर्यात विविधता के लिए नजर रख रही है।

